RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 02 OCTOBER TO 08 OCTOBER 2019 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 6 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

सऊदी अरब ने रिलायंस को पूरी तेल आपूर्ति की प्रतिबद्धता जताई

Page 2

अगले वित्त वर्ष से छोटे व्यावसायियों के लिये 'सहज' जीएसटी रिटर्न फार्म उपलब्ध होगा

Page 3

कीमतों पर अंकुश के लिए प्याज के निर्यात पर रोक

Page 7

editoria!

किन्तु परन्तु के साथ कार्पोरेट कर में कटौती

केंद्र ने कॉर्पोरेट कर में कटौती की घोषणा कर सबको अचरज में डाल दिया है। सरकार ने सभी घरेलू कंपनियों की दर में 10 प्रतिशत तक की कटौती कर उसे 25 प्रतिशत के स्तर पर लाने का फैसला किया है। इसके परिणाम अभी किन्तु परन्तु में फंसे है। कॉर्पोरेट कर राहत की मात्रा एवं रफ्तार भारत के लिए अप्रत्याशित है। रातोंरात हम एशिया के अधिकांश देशों की बराबरी में पहुंच गए हैं। निश्चित तौर पर यह एक अप्रत्याशित कदम था और शेयर बाजारों ने भी पांच फीसदी से अधिक तेजी हासिल की। इस कर राहत के निशाने पर भारतीय कंपनी जगत है और कंपनियों का भरोसा बढ़ाना इसका लक्ष्य है। सरकार ने माना है कि कॉर्पोरेट दिग्गजों के बीच जोखिम से बचने की प्रवृत्ति हावी है। कंपनी अधिनियम में वर्णित कुछ खास अपकृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना भी इसी का हिस्सा है। ब्याज दरों में कितनी भी कटौती कर ली जाए, अगर कंपनी प्रमुखों के मन में भरोसा नहीं है तो निवेश नहीं बढ़ सकेगा। इन कदमों से भारत कारोबार शुरू करने और चलाने के लिए अधिक आकर्षक स्थान बनेगा। वस्तु एवं सेवा कर की दरों में राहत देने से उपभोग को बढ़ावा मिलता लेकिन वित्त मंत्री ने इस उम्मीद में कंपनियों की आय एवं नकदी प्रवाह बढ़ाने की पहल की है कि कंपनियों का भरोसा बढ़ेगा और वे निवेश से नए रोजगार सृजित करेंगी। भारत में कारोबार चलाने से जुड़े गतिरोधों को दूर करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है फिर भी यह एक बड़ा कदम है। अब कर की दरें भारत में निवेश न करने की वजह नहीं रह जाएंगी। कंपनी जगत को अब शिकायती तेवर छोड़कर आगे बढना चाहिए और अर्थव्यवस्था एवं इसकी वृद्धि पर दांव लगाना चाहिए। निश्चित रूप से इस साल के राजकोषीय लक्ष्य सेचूक जाएंगे लेकिन इस कदम का औचित्य तभी साबित हो सकेगा जब वृद्धि पटरी पर आ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सामाजिक कार्यक्रम चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। नई दरें लागू होने के बाद अगर वृद्धि में तेजी नहीं आती है तो फिर उनके पास सामाजिक योजनाओं के लिए फंड नहीं रह जाएगा। इन कर कटौतियों के बाद आर्थिक वृद्धि को लेकर सरकार की चिंताओं के बारे में सारे संदेह दूर हो जाने चाहिए। हर कोई इस पर एकजुट है कि तीव्र आर्थिक वृद्धि आज की अनिवार्यता है। बेहतर बात यह है कि राजकोषीय एवं मौद्रिक प्राधिकारी दोनों ही आखिर एक तरफ हैं। इस वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 3.7-3.8 प्रतिशत तक जा सकता है। शून्य मुद्रास्फीति और कमजोर वृद्धि के दौर में राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत रहने के बजाय मजूबत जीडीपी और आय वृद्धि के साथ बढ़े तो बेहतर होगा। राजकोषीय घाटा बढने से सरकार पर परिसंपत्तियों की तीव्र एवं रणनीतिक बिक्री का दबाव भी बढ़ेगा। रणनीतिक विनिवेश फिर से चर्चा में लौटेगा। और वह पहले की तुलना में अधिक आक्रामक होगा। हम खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी के मामले में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का तीव्र क्रियान्वयन देख सकते हैं क्योंकि व्यय पर लाभ बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा। इस कदम से सरकार ने दिखाया है कि वह सुनने को तैयार है और उसके लिए अर्थव्यवस्था एवं कंपनी जगत मायने रखते हैं। आर्थिक नीतियों के निर्माण में खाली जगह भर दी गई है। सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर बड़े दांव लगाने की मंशा भी दिखाई है। अगले 18 महीनों में GDP एवं कंपनी मुनाफा दोनों में तेजी की उम्मीद की जा सकती है । अभी तो हम हम दोनों मामलों में निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं।

सऊदी तेल रिफाइनरी पर हमले के बाद अमेरिका ने बदला अपना पैट्रियट सिस्टम

दुबई। एजेंसी

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने सऊदी अरब सऊदी अरामको तेल प्लांट पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद अपने यहां लगाए गए पैट्रियट सिस्टम को बदल दिया है। सऊदी अरब ने अपने प्लांट की सुरक्षा के लिए यहां पर दो पैट्रियट सिस्टम लगाए थे लेकिन इसके बावजूद बीते 14 सितंबर को आंतकियों ने मिसाइल और ड्रोन हमले से इस प्लांट को नुकसान पहुंचाया, इस हमले की वजह से प्लांट के दो संयंत्रों को नुकसान पहुंचा था, इसको ठीक करने में कंपनी को एक सप्ताह से अधिक का समय लग गया। अब यहां हुए नुकसान को ठीक करने के बाद फिर से काम शुरु कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सऊदी अरब की ओर से प्लांट की सुरक्षा के लिए जो सिस्टम लगाए गए थे वो कम क्षमता के थे जिसकी वजह से वो यहां पर हुए हमले को नहीं रोक पाए। यदि यहां लगाई गई मिसाइलों की क्षमता अधिक होती है तो इस तरह के हमलों को नाकाम कर दिया जाता। प्रशांत वायु सेना (PACAF) के कमांडर जनरल चार्ल्स ब्राउन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को छोटे परमाणु रिएक्टर हथियारों से लैस करने की योजना बना रहे हैं जिससे आतंकियों के किसी भी हमले को नाकाम किया जा सके। उनका कहना है कि इस तरह के हथियारों से लैस कर दिए जाने के बाद सुरक्षा बेहतर हो सकेगी। उनका सुझाव है कि ऐसे सिस्टम बड़े और भारी इंटरसेप्टर-आधारित सिस्टम से अधिक प्रभावी हो सकते हैं।

जानिए किस तरह का पेट्रोल डीजल है BS-VI

नई दिल्ली। एजेंसी

एनसीआर में 1 अक्टूबर से BS-VI (Bharat Stage Emission Standards) पेट्रोल और डीजल की बिक्री शुरू हो गई है। भारत की सबसे बड़ी तेल विक्रेता कंपनी ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार एक अक्टूबर से हरियाणा के सात जिलों पलवल, गुरुग्राम, नगर, महेंद्र, मेवाद, झज्जर, फरीदाबाद और रेवाड़ी में BS-VI फ्यूल की बिक्री शुरु कर दी गई है।

क्या है BS नॉर्म्स (What is BS Norms)

भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स को साल 2000 में लाया गया था। यह एक एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें केंद्र सरकार तय करती है। ये एमिशन स्टैंडर्ड्स इंटरनल कंबशन इंजन इक्विपमेंट (मोटर व्हीकल शामिल) से निकलने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए तय किए जाते हैं। अलग-अलग नॉर्म्स केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई समयरेखा और मानकों के अनुसार ही लागू किए जाते हैं, जो भारत सरकार एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

क्या है BS-VI के फायदे (Benefits of BS-VI)

BS-VI लागू होने के बाद प्रदूषण को लेकर पेट्रोल और डीजल कारों के बीच ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। पेट्रोल वाली कारों से 25 फीसदी और डीजल वाली कारों से 68 फीसदी तक नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाएगा। साथ ही डीजल कारों से PM (Production Manifold) का उत्सर्जन 80 फीसदी तक कम होने की संभावना बताई जा रही है।

इससे पहले इस साल एक अप्रैल 2019 से राजस्थान के चार जिले करौली, भरतपुर, अलवर और धौलपुर तथा उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, मुज्जफरनगर, गाजियाबाद, शामली, हापुड़, बुलंदशहर और बागपत के साथ ही आगरा शहर में BS-VI पेट्रोल डीजल मिलने लगे थे। सिर्फ हरियाणा के सात जिलों में उनकी उपलब्धता नहीं थी लेकिन अब मंगलवार यानी एक अक्टूबर से शुरू हो गई है । जानिए क्या है Bharat Emmission Standrads अगर कोई गाड़ी अपने तय लिमिट से ज्यादा pollution फैलाता है तो उस गाड़ी को यूरोप में नहीं बेचा जा सकता है। Euro Norms (अनुमानित उत्सर्जन स्तर) जिसे Bharat Stage ने अपनाया है। इसके हिसाब से सभी वाहनों की Pollutant छोड़ने की तय सीमा होना चाहिए। Pollutant का मतलब Nitrogen (NO),CaRon Dioxide (CO2),Suspended Particulate Matter और Sulphur होते है। यह Euro Norms धीरे-धीरे देश के सभी हिस्से में लागू कर दिया जाएगा।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए निगम की तैयारी

पलासिया पर डस्टबिन विक्रय सेंटर प्रारंभ

इंदौर। एजेंसी

देश में साफ सफाई के लिए चल रहे अभियान स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए इंदौर में फिर से प्रथम आए इसके लिए काम शुरू हो गया है। स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जरूरी है घरों से निकलने वाले कचरें को अलग अलग हरे और नीले डस्टबिन में अलग अलग रखा जाए। इसके लिए सस्ते और मजबूत डस्टबिन का आसानी से उपलब्ध होना जरूरी है। इंदौर में आम लोगो को आसानी से डस्टबिन मिले इसके लिए पलासिया पर नगर निगम स्वच्छता सामग्री विक्रय केंद्र स्थापित किया गया है। इसका शुभारंभ गांधी जयंती के अवसर पर नगर पालिक निगम इंदौर के उपायुक्त रजनीश कसेरा ने किया। इस स्वच्छता समाग्री विक्रय केंद्र से हरे-नीले घरेलू डस्टबिन और कार के डस्टबिन के साथ थैला बैंक और होम कम्पोसिट्ंग बिन आम लोगो को विक्रय की जाएगी। इसे इंडियन प्लास्टपैक फोरम और नगर पालिक निगम इंदौर की सहभागिता से लगाया गया है। इंडियन प्लास्टपैक फोरम के मानद सचिव सचिन बंसल ने बताया कि नगर निगम स्वच्छता सामग्री विक्रय केंद्र से हरे नीले डस्टबिन और कार में रखने के लिए डस्टबिन उपलब्ध करवाए गए है। इसी स्थान पर पहले भी डस्टबिन सेंटर लगाया गया था। इन डस्टबिनों

को रिसायकल्ड प्लास्टिक से बनाया गया। पलासिया चौराहे पर लगाए गए इस नगर निगम स्वच्छता सामग्री विक्रय केंद्र के शुभारंभ अवसर पर निगम उपायुक्त रजनीश कसेरा, निगम सलाहकार असद वारसी, इंडियन प्लास्टपैक फोरम के अध्यक्ष व्रजेश गांधी, वरिष्ट सदस्य सुभाष चतुर्वेदी, आरके माहेश्वरी, मेहुल भाई, विकास बांगड सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं और एनजीओ के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

कच्चा तेल आयात कमी होने से मिलेगी पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि जैविक ईंधन कच्चे तेल का आयात कम कर सकता है और इससे हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी जिससे 2025 तक देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। जैसे इथेनॉल और बुटानॉल ना सिर्फ सस्ते हैं बल्कि देश के लिए जरूरी भी हैं क्योंकि यह हमें उत्सर्जन कम करने में मदद करते हैं।

गडकरी ने कहा , ''हम हर साल सात लाख करोड़ रुपये का कच्चा तेल आयात करते हैं। ऐसे में यदि हम जैव ईंधन जैसे कि इथेनॉल और बुटानॉल के विकल्प को अपनाए और इन्हें कारों एवं विमानों में उपयोग करें तो यह ना सिर्फ सस्ते पड़ेंगे बल्कि प्रदूषण मुक्त भी होंगे। हमें इन विकल्पों पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए?'' उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र 40,000 करोड़ रुपये का ईंधन आयात करता है यदि वह जैव ईंधन के विकल्प पर विचार करें तो इससे घरेलू उत्पादकों के लिए 40,000 करोड़ रुपये का बाजार पैदा होगा। उन्होंने कहा कि विमानन जैव ईंधन को अमेरिका और ब्रिटेन में व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाता है। यदि हम भी इसका उपयोग करें तो हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचा सकते हैं। इन कदमों से हमारा तेल आयात कम होगा। वहीं हम कोयले की जगह नेपियर घास का इस्तेमाल करें तो उन्हें भरोसा है कि इससे देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।

सऊदी अरब ने रिलायंस को पूरी तेल आपूर्ति की प्रतिबद्धता जताई

नयी दिल्ली। सऊदी अरब ने अरबपति भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आश्वासन दिया है कि वह अक्टूबर में उसे प्रतिबद्धता के मुताबिक तय मात्रा में कच्चे तेल की पूरी आपूर्ति कर देगा। सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठान अब तक के सबसे बड़े हमले से काफी तेजी से उबर रहे हैं। पहले यह माना जा रहा था कि उन्हें स्थिति को संभालने में काफी समय लग सकता है। रिलायंस ने सऊदी अरब से तेल आपूर्ति के बारे में ईमेल पर पूछे गये सवाल के जवाब में कहा, ''सऊदी अरब की कंपनी आरामको पिछले 20 साल से भी अधिक समय से रिलायंस के लिये कच्चे तेल की भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता रही है। चाहे कच्चे तेल की मात्रा को लेकर हो या फिर विभिन्न श्रेणी के कच्चे तेल की आपूर्ति की बात हो दोनों तरह से आरामको भरोसेमंद रही है। '' रिलायंस ने कहा, ''आरामको के कच्चे तेल प्रतिष्ठानों पर सितंबर मध्य में हुये ड्रोन हमले से हुये नुकसान के बावजूद यह विश्वास बढ़ाने वाला है कि आरामको ने समय के मुताबिक कच्चे तेल की आपूर्ति को बनाये रखा और अपनी आपूर्ति पूतिबद्धताओं को पूरा किया है।''सऊदी अरब के प्रमुख कच्चे तेल प्रतिष्ठानों पर 14 सितंबर को ड्रोन हमला हुआ, इसमें मिसाइल दागे गये जिससे कंपनी का दैनिक 57 लाख बैरल प्रतिदिन के तेल उत्पादन का नुकसान हुआ। यह सऊदी अरब के कुल दैनिक उत्पादा का करीब आधा उत्पादन है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी आरमाको ने नुकसान के बावजूद अपने ग्राहकों को तल आपूर्ति में किसी तरह की कमी नहीं आने दी। उसने अपने रणनीतिक भंडार से आपूर्ति जारी रखी। ड्रोन हमले के बाद भी आरमको ने रिलायंस की जामनगर स्थित दोनों रिफाइनरियों को कच्चे तेल के विभिन्न ग्रेड का आपूर्ति को जारी रखा। रिलायंस ने हालांकि, यह नहीं बताया कि वह सऊदी अरब से कितना कच्चा तेल खरीदती है।

तेल आयात नहीं करने को लेकर भारत से निराश नहीं है ईरानः जयशंकर

वाशिंगटन। एजेंसी

कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों के मद्देनजर ईरान से तेल नहीं खरीदने पर भारत से तेहरान के निराश होने की खबरों को खारिज करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि ईरान के साथ भारत के मजबूत राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंध हैं जहां वह एक रणनीतिक बंदरगाह का भी संचालन करता है। उल्लेखनीय है कि चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में हिंद महासागर में स्थित है। इसे मध्य एशियाई देशों के साथ कारोबार के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान को स्वर्णिम अवसर मुहैया कराने वाले द्वार के तौर पर देखा जाता है। जयशंकर ने 'यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम' के कार्यक्रम में मंगलवार को कहा, ''मैं आपकी इस बात से असहमत हूं कि ईरान निराश है। मेरा मानना है कि ईरानी वास्तविक सोच रखते हैं। वे और हम एक वृहद वैश्विक स्थिति में काम कर रहे हैं। मैं जिस दुनिया में रहता हूं, उसमें हम एक-दूसरे की मजबूरियों और संभावनाओं को समझते हैं।''ईरान से तेल नहीं खरीदने के भारत के फैसले पर ईरानियों के निराश होने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में जयशंकर ने यह प्रतिक्रिया की। उन्होंने खाड़ी में अस्थिरता पर चिंता जताते हुए कहा, ''हमारे नजरिए से असल समस्या यह है कि मुझे किस प्रकार किफायती एवं समय पर तेल एवं गैस की आपूर्ति मिलेगी? अभी तक यह संभव था।'' जयशंकर ने कहा कि ईरान के संदर्भ में भारत की दो चिंताएं हैं। उन्होंने कहा, ''हमारी चिंता यह है कि हम ऊर्जा का आयात करने वाली एक बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और हमारे लिए किफायती एवं समय पर ऊर्जा हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें बार बार यह भरोसा दिलाया गया है कि यह होगा। इसलिए हम इस मानक के साथ क्षेत्र के पास जाएंगे कि हमें ऐसे समाधान की आवश्यकता है जो हमारे लिए कारगर हो। उन्होंने कहा, ''हमारे (ईरान के साथ) मजबूत राजनीतिक संबंध हैं। हमारे बीच सांस्कृतिक संबंध हैं। हम उनके साथ काम करते हैं। हम उस देश में वास्तव में बंदरगाह का संचालन करते हैं, जिससे अफगानिस्तान को लाभ होता है।'' जयशंकर ने कहा कि ऊर्जा, प्रेषण और सुरक्षा या उस क्षेत्र से पैदा होने वाली कट्टरपंथ की चुनौतियों के संदर्भ में भी खाड़ी महत्वपूर्ण है। भारत के लिए इराक और सऊदी अरब के बाद ईरान अब तक तेल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक था।

आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नई स्वच्छ ऊर्जा पहल की शुरुआत करेंगे भारत-अमेरिका

वाशिंगटन। एजेंसी

भारत और अमेरिका रणनीतिक रूप से अहम भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के लिए एक नई पहल शुरू करेंगे। पहल का उद्देश्य इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे के मद्देनजर अमेरिका इस क्षेत्र में भारत की व्यापक भूमिका चाहता है। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा गया कि अमेरिका के ऊर्जा संसाधन विभाग के सहायक सचिव फ्रांसिस आर फेनन 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं। इस दौरान, दोनों देश अमेरिका-भारत स्वच्छ ऊर्जा कोष कार्यबल के तहत फ्लेक्सिबल रिसोर्स इनिशिएटिव एफआरआई की शुरुआत करेंगे। इस संबंध में फेनन, ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, यह पहल भारत-प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि को स्वच्छ ऊर्जा के जरिए बढ़ावा देने के अमेरिका और भारत के साझा विचार को अमल में लाएगी। यह पहल अमेरिका की अगुवाई वाली एशिया एडज ऊर्जा के माध्यम से वृद्धि और विकास को बढ़ाना पहल का हिस्सा है। फेनन के साथ संघीय ऊर्जा विनियामक आयोग, अमेरिका के ऊर्जा विभाग और अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे।

भारत की ओर से ऊर्जा मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग,पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड इस बैठक की मेजबानी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों भारत के लिए राष्ट्रीय बिजली प्रणाली की दिशा में साथ काम करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगे। यह स्थिर, विश्वसनीय और फिकायती होगी।' यह पहल प्राकृतिक गैस एवं बैटरी जैसे संसाधनों के लिए नए निवेश के अवसर मुहैया कराएगी। यह लचीले जरूरत के अनुसार आपूर्ति संसाधनों को अपनाने के साथ-साथ उसके व्यापार को बढ़ाने तथा नियामकीय और नीतिगत व्यवस्था की सुविधा देगा।

अगले वित्त वर्ष से छोटे व्यावसायियों के लिये 'सहज' जीएसटी रिटर्न फार्म उपलब्ध होगा

नयी दिल्ली। एजेंसी

माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के लिये नेटवर्क व्यवस्था उपलब्ध कराने वाली इकाई जीएसटीएन ने उद्योग जगत और खासतौर से छोटे व्यवसायियों को ध्यान में रखते हुये जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के नये सरल फार्म तैयार किये हैं। ये सरल फार्म जीएसटी नेटवर्क की साइट पर उपलब्ध हैं और परीक्षण के तौर पर कारोबारी इन्हें देख और समझ सकते हैं। ये नये फार्म एक अप्रैल 2020 से अमल में आयेंगे। जीएसटीएन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश कुमार ने मंगलवार को मीडिया के समक्ष जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की मौजूदा व्यवस्था और नई फार्म व्यवस्था को लेकर जानकारी उपलब्ध कराई।

उन्होंने बताया कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नई व्यवस्था अगले वित्त वर्ष यानी एक अप्रैल 2020 से शुरू होगी। लेकिन इसके लिये जानकारी और जागरुकता अभियान अभी से शुरू कर दिया गया है ताकि जब इनका वास्तविक इस्तेमाल शुरू हो तो किसी को कोई कठिनाई नहीं हो। उन्होंने बताया कि नई रिटर्न फाइल व्यवस्था में पांच करोड़ रुपये सालाना तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यवसायियों के लिये प्रत्येक तिमाही रिटर्न दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध होगा। कर भुगतान जीएसटी- पीएमटी 08 के तहत ही होगा जबकि पहले यानी मौजूदा चल रही व्यवस्था में यह भुगतान जीएसटीआर-3बी के तहत किया जाता है। पांच करोड़ रुपये सालाना तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों के लिये आरईटी-2 यानी 'सहज' और आरईटी-3 यानी 'सुगम' रिटर्न फार्म तैयार किये गये हैं। इन्हें केवल बी2सी (सीधे ग्राहकों को आपूर्ति करने वाली कंपनियां) और बी2बी (कंपनियों के बीच)तथा बी2सी दोनों तरह का कारोबार करने वालों के आधार पर बांटा गया है। सालाना पांच करोड़ रुपये से अधिक की आपूर्ति करने वाले उद्यमियों को अनिवार्य रूप से आरईटी-1 मासिक रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था होगी। वर्ष 2018- 19 में दाखिल जीएसटीआर-3बी को यदि आधार माना जाये तो सालाना पांच करोड़ रुपये से कम कारोबार करने वाले रिटर्न दाखिल करने वाले व्यवसायियों की संख्या सबसे अधिक 70.22 प्रतिशत तक रही है। इसमें केवल बिजनेस टु कस्टुमर यानी बी2सी आपूर्ति करने वाले कारोबारी 28 प्रतिशत और शून्य कारोबार रिटर्न वालों की संख्या 22.75 प्रतिशत रही है। पांच करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करने वाले उद्यमी जो कि मासिक रिटर्न दाखिल करते हैं उनकी संख्या कुल जीएसटी पंजीकरण संख्या के मुकाबले मात्र 7.06 प्रतिशत रही है।

प्लास्टिक कचरे से निजात दिलाएगा रिफाइनरी प्रबंधन, बनाएगा स्पेशल ग्रेड का डामर

पानीपत। एजेंसी

प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए रिफाइनरी प्रबंधन आगे आया है। इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकिल कर स्पेशल ग्रेड बिटुमेन बनाया जाएगा। इसका उपयोग सड़क निर्माण में होगा। इससे प्लास्टिक कचरे की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक भारत को कचरा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। देश की विभिन्न संगठनों से लेकर देश की नवरत्न कंपनियां इस सपने को साकार करने में जुटी हैं। बिटुमेन तैयार करने के लिए प्लास्टिक रॉ मैटेरियल की जरूरत पड़ती है। रिफाइनरी प्रबंधन ने सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक की थैली) से एक खास किस्म का बिटुमेन बनाने के नए प्लांट का निर्माण किया है। इसमें आधुनिक तकनीक से दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाली प्लास्टिक की थैलियों को रि-साइकिल किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद क्रंब रबड़ मॉडिफाइड बिटुमेन (सीआरएमबी) तैयार होगा। बमुश्किल दो से ढाई फीसद वेस्ट निकलेगा। लैब में परीक्षण के दौरान बिटुमेन का नया ग्रेड सीआरएमबी 55 पी गुणवत्ता में अव्वल क्वालिटी का निकला है। इंडियन आयॅल के चेयरमैन संजीव सिंह बोहली स्थित रिफाइनरी कांप्लेक्स के मार्केटिंग डिविजन में बुधवार दोपहर एक बजे बिटुमेन के इस नए प्लांट का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस दौरान चेयरमैन बिटुमेन को पॉलीबैग में पैक करने के प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ने इसे विकसित किया है। रिफाइनरी सूत्रों के मुताबिक पॉलीबैग बनाने में सौ फीसद सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा। सड़क निर्माण के दौरान पॉलीबैग बिटुमेन में यह पूरी तरह घुलनशील होगा। रिफानरी के सूत्रों के मुताबिक वेस्ट प्लास्टिक मैटेरियल की आपूर्ति एनजीओ करेगा। एनजीओ इसे कचरा बीनने वालों से लेकर रिफाइनरी को देंगे।

प्लास्टिक उद्योग को मिली राहत की सांस

- **केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध नही लगाया**
- **जनजागरण और जारी नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा।**
- **इंडियन प्लास्टपैक फोरम की कोशिश पर दिल्ली में हुआ विचार**

इंदौर। देश में 2 अक्टुबर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर चल रहा संयश अब खत्म हो गया है। प्लास्टिक उद्योगों को किसी नए नियम, प्रतिबंधित होने वाले प्रोडक्ट की जानकारी नही मिल पा रही थी। अब जब केंद्र सरकार ने नए नियम के स्थान पर पहले से लागू नियमों के तहत ही कार्यवाही और जनजागरण के माध्यम लागू करने का निणर्य लिया है। इससे प्लास्टिक उद्योग ने राहत की सांस ली है। इस संबध में प्लास्टिक उद्योग का मुख्य संगठन इंडियन प्लास्टपैक फोरम ने भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मप्र पर्यावरण एवं आवास मंत्रालय, मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल सहित इंदौर नगर पालिक निगम को भी ज्ञापन दिया था। आईपीपीएफ के श्री सचिव सचिन बंसल ने बताया कि केंद्र सरकार से अपील की गई थी कि वे वर्तमान में स्थापित उद्योग में हुए निवेश, उनमें लगे लोगो के रोजगार और प्लास्टिक का कोई विकल्प नही होने के चलते सरकार से इसे लागू करने के पहले फिर से विचार करने की बात कही थी। इस संदर्भ में आईपीपीएफ के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर गंभीरता से विचार किया गया। उन्होनें बताया कि हमारे द्वारा दिए गए प्रजेंटेशन में उद्योगो की संख्या, निवेश, रोजगार और पूंजी की हानि के आंकडे से केंद्र और प्रदेश के अधिकारी भी सहमत हुए। श्री बंसल ने बताया कि अब केंद्र सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक को विभिन्न चरणों में रोक लगाएगी। इससे उद्योगो को संभलने का मौका मिलेगा। सचिव श्री बंसल ने बताया कि इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के प्रतिवेदन के बाद अब विस्तृत जानकारी के साथ एक बार फिर से मिलने लिए बुलाया गया है। इसमें कैसे प्लास्टिक के सिंगल यूज प्रोडक्टर्स को रिसायकलिंग बढाने, उनके निष्पादन के तरीके और रोक लगाने की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। उन्होनें सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्टर्स पर तत्काल रोक नही लगाने के लिए केंद्र और राज्य शासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि अधिकारियों ने हमारी समस्या को समझा और उसे माना है अब प्लास्टिक उद्योग इस दिशा में हर संभव मदद करेगें और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 और संसोधन नियम 2018 के तहत लागू नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

RCEP में 80% चाइनीज इंपोर्ट पर टैक्स ड्यूटी घटा सकता है भारत

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत 16 देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार संधि के तहत चीन से मंगाए जाने वाले 80% सामान पर लगने वाले आयात शुल्क में कटौती कर सकता है या उसे पूरी तरह खत्म कर सकता है। इसके लिए ताइवान में अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। हालांकि, चीन से आयातित सामान पर दी जाने वाली रियायत रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप (RCEP) के दूसरे देशों को ऑफर की गई रियायत से कम हो सकती है क्योंकि भारत नहीं चाहता कि एग्रीमेंट पर साइन होने के बाद देश में सस्ते चाइनीज माल की बाढ़ न आ जाय।

RCEP एसोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशंस (ASEAN) के 10 सदस्य देशों और उसके छह FTA पार्टनर्स- चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार संधि है। RCEP के लिए बातचीत नवंबर 2012 से चल रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मंगाए जाने वाले 86% सामान और आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया से आनेवाले 90% माल से आयात शुल्क घटाने की योजना बनाई है।

आधिकारिक सूत्र ने कहा, 'चीन के साथ बातचीत जारी है और इस पर काम चल रहा है। हमने ऑफर

को अंतिम रूप नहीं दिया है।' योजना के मुताबिक भारत चीन से मंगाए जाने वाले 28% सामान पर लगने वाली कस्टम्स ड्यूटी तुरंत हटाएगा, जबकि दूसरे सामान पर लगने वाला आयात शुल्क 5, 10, 15 और 20 साल में घटाया या खत्म किया जाएगा। इससे भारत को अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। सरकार ने 20 सितंबर को एक बड़े टैक्स रिफॉर्म में नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के वास्ते निवेश आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 15% कर दिया था। सरकारी अधिकारी ने कहा, 'कुछ उत्पादों और देशों को संधि के दायरे में लाने के लिए हम 20 साल से भी ज्यादा समय से कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे प्रॉडक्ट्स हो सकते हैं जिन पर लग रहे टैरिफ को तुरंत खत्म किया जाएगा।' सूत्रों ने बताया कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को सख्त बनाने के प्रस्ताव पर भारत को ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। भारत इसके जरिए RCEP के दूसरे सदस्य देशों के रास्ते चीन का माल देश में आने पर रोक लगाना चाहता है।

रूल्स ऑफ ओरिजिन एक तरीका है जिसमें यह बताया जाता है कि सामान किस देश में बना है। सामान पर आयात शुल्क लगाने या उसमें रियायत की पेशकश करने का फैसला इसी आधार पर किया जाता है। भारत ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि जिस देश से सामान सीधे आ रहा है, वहां स्थानीय सामग्रियों के जरिए उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन होना चाहिए। रूल्स ऑफ ओरिजिन को सख्त बनाया जाना भारत के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि RCEP के 11 सदस्य देशों के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट है। चीन के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट 2018-19 में 53.6 अरब का था।

छंट गए हैं इकॉनमी पर छाए काले बादल!

GST और ऑटो सेल्स ने दिया रिकवरी का सिग्नल

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कंज्यूमर सेंटिमेंट अभी भी कमजोर है, इसलिए आर्थिक रिकवरी में वक्त लगेगा। हालांकि, इस बीच मंगलवार को आए कई आर्थिक आंकड़ों से अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा वक्त खत्म होने के संकेत मिले हैं। सितंबर में दिग्गज कार कंपनियों की बिक्री में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा, लेकिन अच्छी

बात यह है कि इसकी रफ्तार धीमी पड़ी है। कुछ कंपनियों की बिक्री में तो अगस्त की तुलना में सितंबर में बढ़ोतरी हुई है। सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 51.4 के साथ इससे पिछले महीने के स्तर पर रहा, लेकिन गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन गिरकर 19 महीने के सबसे निचले स्तर पर चला गया। उधर, ई-कॉमर्स कंपनियों ने बताया कि चालू फेस्टिव सीजन में ग्राहकों की खरीदारी में दिलचस्पी बनी हुई है।

ऑटो सेक्टर में ग्रीन सिग्नल

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की बिक्री सितंबर में सालाना आधार पर 27.1% गिरकर 110,454 यूनिट पर आ गई, लेकिन यह अगस्त से 18.5% अधिक है। बड़ी बात यह है कि पिछले महीने श्राद्ध का पखवाड़ा चला, जिसमें हिंदू मान्यताओं के मुताबिक मकान और गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी से परहेज किया जाता है। मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर केनिचि अयुकावा ने कहा, 'अगस्त के मुकाबले सितंबर बेहतर रहा। हम अक्टूबर के सितंबर से बेहतर रहने की उम्मीद कर रहे हैं।' कमर्शल वीइकल कंपनी टाटा मोटर्स का सेल्स वॉल्यूम सालाना आधार पर 45.4% गिरकर 28,079 यूनिट पर आ गया, लेकिन मासिक आधार पर इसमें 28.7% की बढ़ोतरी हुई।

अगस्त के हैं GST के आंकड़े, आगे सुधार

ऑटो सेक्टर से मिली अच्छी खबरों के बीच सितंबर के GST कलेक्शन डेटा ने निराश किया। अगस्त में 98,202 करोड़ रुपये रहा कलेक्शन सितंबर में गिरकर 91,916 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि GST कलेक्शन के आंकड़े अगस्त में हुए ट्रांजेक्शंस के हैं, ऐसे में ऑटो सेल्स में मासिक आधार पर हुई बढ़ोतरी से आने वाले समय में इसमें सुधार होगा।

मैन्युफैक्चरिंग में भी सुधार की उम्मीद

सुस्त मांग से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के प्रॉडक्शन पर दबाव बना हुआ है, जिसकी गवाही PMI डेटा दे रहे हैं। बिजनस कॉन्फिडेंस भी ढाई साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसके बावजूद इश्ध सर्वे से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सेहत में सुधार के संकेत मिले हैं। इसे तैयार करने वाली एजेंसी IHS मार्किट ने कहा है कि सरकारी उपायों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रफ्तार पकड़ सकता है।

सुस्ती के बाद सरकार ने की थी उपायों की घोषणा

जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ छह साल के निचले स्तर 5% पर आ गई थी। इसके बाद सरकार ने आर्थिक रफ्तार तेज करने के लिए कई उपायों का ऐलान किया था। कॉरपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया, जबकि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 15% तय किया गया है।

मोदी सरकार ने छोटे कारोबारियों को दिया तोहफा!

सिर्फ SMS से भरें GST रिटर्न

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। आगामी 1 अप्रैल, 2020 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) असेसी अपने फोन से सिर्फ एसएमएस (SMS) भेजकर जीएसटी रिटर्न (GST Return) फाइल कर सकेंगे। इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए एकमात्र शर्त यह है कि उनका टर्नओवर निल होना चाहिए। इसके अलावा छोटे कारोबारियों को तीन महीने में सहज (SAHAJ) और सुगम (SUGAM) फार्म से तीन महीने में एक बार रिटर्न दाखिल करना होगा। जीएसटी नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) प्रकाश कुमार ने कहा कि जीएसटी नंबर लिया हुआ है और इसके तहत रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता के चलते उन्हें रिटर्न दाखिल करना पड़ता है. इनके लिए नई प्रणाली में एक विशेष श्रेणी बना दी गई है। ऐसे करदाता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से सिर्फ एसएमएस भेज कर अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।

SMS से भर जाएगा जीएसटी रिटर्न

रिपोर्ट के मुताबिक, नए सिस्टम के तहत निल टर्नओवर वाले असेसी को सिर्फ SMS भेजना होगा और उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा। इस ओटीपी को वापस भेजने पर उनका रिटर्न दाखिल किया हुआ माना जाएगा।

ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन फेल होने पर फैलीं तरह-तरह की अफवाहें लेकिन ये थी असली वजह

नई दिल्ली। एजेंसी

प्राइवेट बैंकों के हजारों खातों से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फेल होने पर मंगलवार को अफवाहों का बाजार गरम हो गया। अफवाहों को बल इसलिए भी मिला क्योंकि जब बैंकों के सर्वर डाउन हुए थे तब बैंकों के संकट और बैंक शेयरों में गिरावट की कई खबरें आ रही थीं। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर कयासों की बाढ़ आ गई। इससे संबंधित बैंकों में पैसे जमा कर रखे लोग चिंतित होने लगे। हालांकि, हकीकत यह थी कि ऑनलाइन पेमेंट पर ऑफर्स और 1 तारीख होने की वजह से सैलरी जारी किए जाने के कारण ट्रैफिक बढ़ गया था जिससे सर्वर डाउन हो गया था।

आरबीआई को देना पड़ा आश्वासन

सबसे पहले पंजाब ऐंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों में खलबली मची और फिर यस बैंक को लेकर आई निगेटिव रिसर्च रिपोर्ट ने उसके ग्राहकों को भी परेशान कर दिया। स्थिति को भांपते हुए रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने तुरंत बयान जारी किया। उसने ट्वीट कर कहा, 'सहकारी बैंकों सहित कुछ बैंकों को लेकर कुछ जगहों पर अफवाहें चल रही हैं। इससे बैंकों में पैसे जमा करने वाले लोग चिंतित हैं। केंद्रीय बैंक आम लोगों को आश्वस्त करना चाहता है कि भारतीय बैंक प्रणाली सुरक्षित और स्थिर है। ऐसी अफवाहों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है।' आरबीआई ने कहा कि बैंकों के बंद होने की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें।

भारतीय बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित, घबराने की जरूरत नहीं: आरबीआई इन बैंकों के फेल हुए थे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन

दरअसल, पीएमसी बैंक में घोटाले के पीड़ितों के विडियो भी मंगलवार को वायरल हो रहे थे। इसी बच यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे कई प्राइवेट बैंकों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फेल होने लगे जिससे ग्राहकों की आशंका बढ़ने लगी। लोग ट्रांजैक्शन फेल होने पर बताने लगे कि वे किराया देने, स्कूल फी भरने और दूसरी जरूरतों के लिए पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं।

बैंकों ने सफाई में क्या कहा

बैंकों ने बताया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फेल होने का असल कारण त्योहारी मौसम में जमकर हो रही खरीदारी, ई-कॉमर्स साइटों द्वारा ऑनलाइन पेमेंट पर दिए गए ऑफर और 1 तारीख को वेतन भुगतान दिवस का होना था। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि बैंक अब ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अतिरिक्त सर्वर डिप्लॉय करेगा।

वहीं, एचडीएफसी बैंक के प्रवक्ता ने बताया कि शाम तक सर्वर सही तरीके से काम करने लगा था। एचडीएफसी बैंक ने भी सोमवार को फेस्टिवल ऑफर लॉन्च किया था। हालांकि, यस बैंक ने सर्वर डाउन होने के सवाल पर कोई टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन उसने अपने ग्राहकों को बताया था कि नेटबैंकिंग की समस्या तात्कालिक है जो जल्द खत्म हो जाएगी। बाद में उसने आरबीआई के ट्वीट को रीट्वीट भी किया।

सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का बड़े पैमाने इस्तेमाल करेगी सरकार

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सड़क निर्माण में सरकार बड़े पैमाने पर प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल करेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के मुताबिक मंत्रालय राजमार्ग निर्माण में विशेषकर पांच लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के 50 किलोमीटर के दायरे में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में प्लास्टिक कचरे के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरे का बड़े पैमाने पर उपयोग करने के लिए एक मिशन 'स्वच्छता ही सेवा' शुरू किया है। उसने देशभर में करीब 26,000 लोगों को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के बारे में जागरुक किया है। प्लास्टिक कचरे के संग्रहण में 61,000 घंटे का श्रमदान किया है। इसके तहत देशभर में 18,000 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे का संग्रह हुआ है।

सिर्फ 25 सेकंड बजेगी एयरटेल ग्राहकों के फोन की घंटी

नयी दिल्ली। एजेंसी

अभी आपके मोबाइल पर जब कोई कॉल आती है तो उसकी घंटी 35 से 40 सेकंड तक सुनायी देती है। लेकिन एयरटेल ग्राहकों के फोन पर घंटी बजने की अवधि 25 सेकंड हो गयी है। प्रतिद्वंदी रिलायंस जियो से बराबरी के लिए कंपनी ने यह निर्णय किया है। इसका एक मकसद कॉल जुड़ने पर लगने वाले इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क आईयूसी की लागत घटाना भी है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इंटरकनेक्ट शुल्क पर उसके किसी आधिकारिक निर्णय पर पहुंचने से पहले इस मुद्दे पर आपस में उलझी दूरसंचार कंपनियों से सर्वसम्मति से किसी समाधान पर पहुंचने के लिए कहा था। इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जुड़ने के लिए लिया जाता है। इसमें जिस नेटवर्क से कॉल की जाती है वह कॉल पहुंचने वाले नेटवर्क को यह शुल्क अदा करता है। अभी इसकी दर छह पैसा प्रति मिनट है।

एयरटेल ने कहा कि उसने फोन की घंटी बजने की अवधि को 25 सेकंड तक सीमित करने का निर्णय किया है। जियो के ऐसा करने के बाद यह फैसला लिया गया है। इससे ग्राहकों को असुविधा हो सकती है। नियामक की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश ना होने के चलते कंपनी के पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। हालांकि कंपनी नियामक के सामने इस बात को कई बार रख चुकी है। ट्राई से जुड़े सूत्रों ने बताया कि नियामक 14 अक्टूबर को 'कॉल किए जाने वाले व्यक्ति को फोन की घंटी बजने की अवधि' के मुद्दे पर एक खुली चर्चा कराने की योजना बना रहा है। इसके अलावा इस पूरे आईयूसी मुद्दे पर भी बातचीत होगी। इसके लिए एक परिचर्चा पत्र पहले ही जारी कर दिया गया है। इस पर जल्द निर्णय किया जाएगा। एयरटेल ने ट्राई को 28 सितंबर को भेजे एक पत्र में कहा, यद्यपि हमने महसूस किया कि इससे ग्राहकों को परेशानी हो सकती है लेकिन ट्राई की ओर से कोई निर्देश नहीं होने और इंटरकनेक्ट शुल्क के घाटे से बचने के लिए हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। इसलिए हमने हमारे नेटवर्क पर फोन की घंटी बजने की अवधि को घटाने का निर्णय किया है। एयरटेल ने कहा,पिछले सात-आठ हफ्तों में कई अनुरोध के बावजूद ट्राई ने रिलायंस जियो को फोन की घंटी की अवधि बढ़ाकर मूल रूप में लाने का निर्देश नहीं दिया है। ना ही उसने अधिकतर कंपनियों द्वारा सहमत 30 सेकंड की अवधि लागू करने के लिए कोई सामान्य निर्देश दिया है।'' एयरटेल ने जियो के इस कदम के प्रभाव के बारे में बार-बार ट्राई को बताया है। कंपनी का कहना है कि फोन की घंटी बजने की अवधि कम करने से मिस्ड कॉल की संख्या बढ़ेगी। इससे किसी व्यक्ति को कॉल लगाने और साथ ही मिस्ड कॉल देखने के बाद वापस कॉल करने की संख्या भी बढ़ेगी। इससे ग्राहकों के अनुभव के साथ-साथ नेटवर्क की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कंपनी का कहना है कि इससे ग्राहकों के लिए कॉल को दूसरे नंबर पर स्थानांतरित कॉल फारवर्ड करने की सुविधा लेना भी मुश्किल हो जाएगा। पिछले महीने आईयूसी के मुद्दे को लेकर सभी कंपनियों का विवाद नियामक के पास तक पहुंच गया था। एयरटेल ने दूसरे नेटवर्क पर कॉल जुड़ने को पैसा कम चुकाने के लिए जियो पर प्रणाली के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। वास्तव में आईयूसी को एक जनवरी, 2020 से खत्म किए जाने का प्रस्ताव है। लेकिन ट्राई इस समयसीमा की अभी समीक्षा कर रहा है।

सात प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री 14 प्रतिशत बढ़ी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

चालू कैलेंडर वर्ष के पहले नौ महीनों (जनवरी-सितंबर) में घरों की बिक्री 14 प्रतिशत बढ़ी है। जेएलएल द्वारा मंगलवार को जारी भारतीय रियल एस्टेट बाजार के बारे में 2019 की तीसरी तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के बाद 2018 में आवास बाजा की स्थिति कुछ सुधरी थी। चालू साल के पहले नौ माह में शीर्ष सात रियल एस्टेट बाजारों में घरों की बिक्री सुधरी है लेकिन यह नोटबंदी पूर्व के स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। हालांकि इस दौरान कार्यालय स्थल की मांग में 40 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान घरों की बिक्री नोटबंदी से पूर्व के दौर के स्तर को नहीं छू पाई। उस समय शीर्ष सात बाजारों में लगभग 1,20,000 आवासीय इकाइयों की बिक्री हुई थी। इसकी तुलना में इस साल जनवरी-सितंबर की अवधि के दौरान देश के प्रमुख सात बाजारों में 1,15,000 इकाइयों की बिक्री दर्ज की गई है।

मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली-एनसीआर का कुल बिक्री में 60 प्रतिशत हिस्सा रहा। 2019 की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान, बिक्री की गति 2018 की इसी अवधि की तुलना में समान रही। तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर नए परियोजनाओं ककी शुरुआत में चार प्रतिशत की गिरावट आई। कुल नई शुरू परियोजनाओं में मुंबई और बेंगलुरु का हिस्सा 60 प्रतिशत रहा। शीर्ष सात शहरों में दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता शामिल हैं। इस रिपोर्ट को पेश करने के मौके पर जेएलएल इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कंट्री प्रमुख रमेश नायर ने कहा, '2018 में घरों की बिक्री में देखी गई बढ़त 2019 के दौरान भी कायम है। डेवलपर पहले से शुरू परियोजनाओं की समय पर आपूर्ति करने पर ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा वे अपने बिक नहीं सके घरों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक ने नीतिगत दरों में जो कटौती की है उसका पूरा लाभ ग्राहकों को अभी नहीं मिल पाया है। बैंक धीरे-धीरे ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं और नया कर्ज दे रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि त्योहारी सीजन में रियल एस्टेट क्षेत्र अच्छी बिक्री दर्ज करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेवलपर्स ने मध्य और किफायती खंडों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है।

12 राशियों की हैं अलग देवियां, जानिए आपकी देवी कौन सी हैं

शारदीय नवरात्रि 2019 में राशि के अनुसार देवी का चयन कर साधना की जाए तो हर क्षेत्र में मनचाही अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। राशि के अनुसार जानिए आपकी देवी कौन सी हैं...

(1) मेष राशि : इस राशि के जातक भगवती तारा, नील-सरस्वती या माता शैलपुत्री की साधना करें।

(2) वृषभ राशि : इस राशि के जातक भगवती षोडशी-श्री विद्या की साधना करें या माता ब्रह्मचारिणी की।

(3) मिथुन राशि : इन्हें माता भुवनेश्वरी की या माता चन्द्रघंटा की उपासना करनी चाहिए।

(4) कर्क राशि : कर्क राशि के जातकों को माता कमला अथवा माता सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए।

(5) सिंह राशि : इन्हें माता पीताम्बरा या माता कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए।

(6) कन्या राशि : इन्हें माता भुवनेश्वरी या माता चन्द्रघंटा की उपासना करनी चाहिए।

(7) तुला राशि : इन्हें श्री विद्या में माता षोडशी या माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए।

(8) वृश्चिक राशि : इन्हें भगवती तारा या माता शैलपुत्री की उपासना करनी चाहिए।

(9) धनु राशि : इन्हें माता मंगला या माता सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए।

(10) मकर राशि : इन्हें माता जयंती या माता सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए।

(11) कुंभ राशि : इन्हें माता भद्रकाली या माता सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए।

(12) मीन राशि : इन्हें माता कमला या माता सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए।

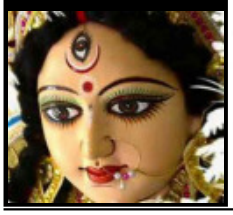

शारदीय नवरात्र- अध्यात्म पथ की प्रथम सीढ़ी

नवरात्रि उत्सव की प्रासंगिकता

वैदिक विज्ञान के अनुसार यह सृष्टि एक चक्रीय धारा में चल रही है, किसी सीधी रेखा में नहीं। प्रकृति के द्वारा हर वस्तु का नवीनीकरण हो रहा है। हर रात्रि के बाद दिवस है तो दिवस के बाद रात्रि। हर पतझड़ के बाद बसंत आती है तो बसंत के बाद पतझड़ निश्चित है। यहां जन्म और मृत्यु भी चक्राकार में है और सुख के बाद दुख तो दुख के पश्चात सुख भी निश्चित चल रहा है। प्रकृति की स्थूल से सूक्ष्म तक की सभी रचनाएं पुरातन से नवीन और नवीन से पुरातन के चक्रीय मार्ग का ही अनुसरण कर रही है। नवरात्रि का त्यौहार भी मनुष्य के मन व बुद्धि को संसार की दौड़ में से लौट कर स्वयं की खोज का एक सुअवसर है।

नवरात्रि पर्व की सनातन धर्म संस्कृति में अनुपम महिमा है, धार्मिक और सात्विक व्यक्तियों के लिए यह एक धार्मिक यात्रा के समान है। श्रावण मास में देवों के देव महादेव को प्रसन्न कर साधक प्रसन्न होते हैं, इसके बाद माता सती, पार्वती और शिव की शक्ति को प्रसन्न करने के लिए शारदीय नवरात्रि में पूजन कार्य किए जाते हैं। उत्सव की यह नौ रात्रियां, प्रकृति की मनुष्य को वह भेंट है, जब मनुष्य अपने भीतर की मलिनता को पहचान कर हटाने का उद्यम करता है। परिणामस्वरूप मनुष्य के भीतर इन नवरात्रियों में नवनिर्माण का आध्यात्मिक कार्य गतिशील होता है। 29 सितम्बर 2019 से शरद नवरात्र आरम्भ हो चुके हैं और 7 अक्तूबर 2019 को इनका समापन हो जाएगा। नवरात्रि में व्रत, उपवास, साधना और पूजा-पाठ करने का धार्मिक महत्व है।

मौन, प्रार्थना, सत्संग और ध्यान

संसार में भटकते चित्त को स्वयं के स्रोत तक वापस लौटने के लिए मौन, प्रार्थना, सत्संग और ध्यान के मूलभूत आधार चाहिए। मौन हमारे मन की भटकन को दूर करता है तो प्रार्थना से यही मन ईश्वर में एकाग्र होने की चेष्टा करता है। सत्संग में ईश्वर के स्वरूप का सही निर्णय होता है और साधना का सम्पूर्ण मार्ग श्री गुरु सत्संग के माध्यम से ही उजागर करते हैं। तत्पश्चात ध्यान की सम्यक विधियों के द्वारा मनुष्य अपने मूल स्रोत (सत् चित्त आनंद) की ओर गमन करते हुए परम रहस्य का साक्षात्कार करता है।

एक आंतरिक यात्रा

नवरात्रि का यह उत्सव मनुष्य के भीतर आतंरिक यात्रा करके नवीनीकरण को प्रकट करने का उत्सव है। यह समस्त ब्रह्मांड एक ही शक्ति से उत्पन्न हुआ है, संचालित हो रहा है और उस एक ही शक्ति में विलय को प्राप्त होगा। इसी शक्ति को हम आद्य शक्ति कहते हैं। इस शक्ति को असंख्य नाम रूपों से गाया और पूजा गया है। कोई इसे मात्र देवी कहता है और कोई शक्ति। कोई देवी और शक्ति को दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी आदि के नाम और विविध रूप से पूजता है परंतु हर मान्यता देवी को मां मानती है क्योंकि समस्त जड़ व चेतन पदार्थों की उत्पत्ति इस एक ही शक्ति में से हुई है और महा-विलय के पश्चात सब कुछ इस एक शक्ति में ही खो जाता है। नवरात्रि का उत्सव इस एक शक्ति, आद्य शक्ति को उजागर करने का सुअवसर है। वैसे तो यह शक्ति इस ब्रह्मांड के कण-कण में सक्रिय है परंतु मनुष्य इस महा-रहस्य से अपरिचित है क्योंकि तमस-रजस-सत्व गुणों की त्रिगुणात्मकता में ही मनुष्य का मन उलझा हुआ है।

तीन गुणों का शुद्धिकरण

नवरात्रि के ये नौ दिन हमारे मन में रहे इन तीन गुणों का शुद्धिकरण करने के दिन हैं। तमस-रजस-सत्व से गुंथी हुई मनुष्य की प्रकृति अज्ञानता और मोह के कारण परिभ्रमण में उलझी हुई है। इन नौ-दिनों में क्रमशः इन तीन प्रकृतियों में शुद्धिकरण करके मनुष्य के भीतर नव-निर्माण की संभावना को दृढ़ करना है। नवरात्रि उत्सव के संबंध में कुछ कथाएं भी प्रचलित हैं।

राम और रावण के बीच जब युद्ध होने वाला था। उससे पहले ब्रह्मा जी ने देवों के माध्यम से श्री राम से रावण वध के लिए देवी चंडी की एक सौ आठ 'नीलकलम' के द्वारा पूजा करके प्रसन्न करने को कहा। परामर्श के अनुसार श्री राम ने पूजा के लिए हवन सामग्री और 108 नीलकमल की व्यवस्था की परंतु रावण ने अपनी मायावी शक्ति से हवन सामग्री और 108 नीलकमल गायब कर दिए और श्री राम को जब अपना संकल्प टूटता नजर आने लगा तो उसी समय उन्हें स्मरण आया कि लोग मुझे 'कमल नयन-नवकंच-लोचन' भी कहते हैं। उसके बाद श्री राम ने अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए नेत्र अर्पित करने का निर्णय लिया और जैसे तीर को आंख के पास ले गए वैसे ही देवी चंडी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और विजयी होने का आशीर्वाद दे दिया।

दूसरी ओर रावण ने भी चंडी देवी की पूजा का आयोजन किया था और ब्राह्मणों को बुलाया था। हनुमान जी ने भी बालक ब्राह्मण का रूप रख कर अन्य ब्राह्मणों की खूब सेवा की और ब्राह्मणों ने खुश होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने पूजा में होने वाले मंत्र में एक अक्षर बदलने का वरदान मांग लिया जिससे पूजा कार्य अच्छे से सम्पन्न नहीं हो पाया और रावण को विजयश्री का आशीर्वाद नहीं मिला। इससे शक्ति देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की घोर तपस्या करके और उनसे वरदान मांग कर महिषासुर बड़ा ही ताकतवर हो गया। उसके बाद वह स्वर्ग पर आक्रमण करके वहां का स्वामी बन बैठा और देवराज इंद्र सहित सारे देवताओं को वहां से निकाल दिया। वह देवताओं, मनुष्यों और अन्य जीवों पर अत्याचार करने लगा। वह इतना ताकतवर था कि उसका सामना करना संभव नहीं था।

सभी देवताओं ने इससे दुखी होकर भगवान विष्णु से इसका उपाय पूछा। तब विष्णु जी के सुझाव से सभी देवताओं ने अपनी शक्ति और अस्त्र देवी दुर्गा को दिए जिससे वह दुष्ट महिषासुर का वध कर सकी, इससे देवी दुर्गा बहुत शक्तिशाली हो गई। नौ दिन तक देवी-महिषासुर संग्राम हुआ और अंत में महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए शक्ति रूप मां दुर्गा की पूजा और अर्चना बड़े धूमधाम से की जाती है। **—आचार्य रेखा कल्पदेव**

कीमतों पर अंकुश के लिए प्याज के निर्यात पर रोक

व्यापारियों के लिए स्टॉक की सीमा तय

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने प्याज की कीमतों में उछाल के बीच हर किस्म के प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ायी ला सके। इसके साथ साथ इसकी जमाखोरी रोकने के लिए प्याज के खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए भंडारण या स्टॉक की सीमा घोषित कर दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में कहा कि खुदरा व्यापारियों के लिए प्याज भंडारण की सीमा 100 क्विंटल तक तय की गई है। वहीं थोक व्यापारी 500 क्विंटल तक प्याज का स्टॉक रख सकेंगे। साथ ही राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे प्याज जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश और श्रीलंका को न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) से कम पर निर्यात को तत्काल रोका जाएगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगस्त से प्याज की कीमतों में उछाल आया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्याज का खुदरा दाम 60 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र जैसे प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में बाढ़ की वजह से इसकी आपूर्ति प्रभावित हुई है। बयान में कहा गया है कि बाजार में प्याज की ऊंची कीमतों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है, व्यापारियों के लिए प्याज के स्टॉक की सीमा लागू की गई है और राज्य सरकारों से जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अधिसूचना में कहा, ''सभी किस्म के प्याज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।'' डीजीएफटी आयात और निर्यात से संबंधित मुद्दों को देखता है। इससे पहले 13 सितंबर को डीजीएफटी ने प्याज के निर्यात पर अंकुश के लिए 850 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) तय किया था। इस कदम का उद्देश्य घरेलू बाजार में प्याज कीमतों पर अंकुश लगाना था। कोई भी निर्यातक एमईपी से नीचे के भाव पर निर्यात नहीं कर सकता है। राज्य सरकारों के पास स्टॉक की सीमा तय करने का अधिकार होता है। लेकिन इस बार केंद्र ने सीधे राज्यों पर स्टॉक की सीमा लागू की है। केंद्र ने राज्यों को प्याज भंडारण की सीमा को कड़ाई से लागू करने और जमाखोरों के खिलाफ अभियान चलाने को कहा है। इस बीच, उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र सरकार अपने बफर स्टॉक से 50,000 टन प्याज निकाल रही है। दिल्ली में मदर डेयरी और सहकारी कंपनियों नाफेड और एनसीसीएफ द्वारा 23.90 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी वाली दर से प्याज की बिक्री की जा रही है। अन्य राज्यों से भी कहा गया है कि वे केंद्र के बफर स्टॉक का इस्तेमाल आपूर्ति बढ़ाएं। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख राज्यों में बाढ़ की वजह से प्याज की आपूर्ति प्रभावित हुई है।

सरकार को नये कीटनाशक विधेयक में उद्योग की चिंताओं को संबोधित करना चाहिये: क्रॉपलाईफ

नयी दिल्ली। एजेंसी

क्रॉपलाइफ इंडिया के अध्यक्ष राजेंद्र वेलागाला ने कहा कि सरकार को कीटनाशक प्रबंधन विधेयक में कीटनाशक उद्योग की चिंताओं को दूर करना चाहिए। इस विधेयक के संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पारित होने की संभावना है। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, जो कीटनाशक अधिनियम, 1968 की जगह लेगा। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक में कीमतों को तय करके और एक नियामक प्राधिकरण की स्थापना करके कीटनाशक क्षेत्र को विनियमित करने की कोशिश की गई है। वेलागाला ने कंपनी की 39 वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ''सरकार को कीटनाशक प्रबंधन विधेयक में कीटनाशक उद्योग की चिंताओं का समाधान करना चाहिए।'' सरकार ने एक बयान में कहा, सरकार को डेटा संरक्षण व्यवस्था लाकर तथा फसल सुरक्षा उत्पादों की पंजीकरण समय सीमा को कम करते हुए इसे सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाना चाहिये और नियामक सुधारों के साथ उसका अनुकूलन करना चाहिए। वेलागला ने कहा कि डिजिटलीकरण से दक्षता आयेगी और इसको अपनाने की गति हमारी प्रगतिशील नीतियों पर निर्भर करेगा। क्रॉपलाइफ, फसल संरक्षण के क्षेत्र में 18 अनुसंधान और विकास-उन्मुख सदस्य कंपनियों का एक संघ है।

रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय के सचिव पी राघवेंद्र राव ने कहा, ''भारत में खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में कृषि रसायन की भूमिका महत्वपूर्ण है, विशेषकर इस तथ्य की रोशनी में यह महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि वर्ष 2030 तक भारत के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाने का अनुमान है।'' कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार जल्द ही फसल सुरक्षा उत्पादों के उपयोग के लिए ड्रोन का उपयोग करने के बारे में दिशानिर्देश जारी करेगी। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव (बीज और मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी) अश्विनी कुमार ने कहा, ''भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ड्रोन द्वारा फसल सुरक्षा उत्पादों के अनुप्रयोग पर एक अध्ययन कर रही है और रिपोर्ट जल्द ही मंत्रालय को सौंपी जाएगी।'' उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस दिशा में नजदीकी तालमेल के साथ काम कर रहा है और जल्द से जल्द ड्रोन अनुप्रयोगों के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।

ट्राई ने एमएनपी सेवा के लिए शुल्क घटाकर 6.46 रुपये किया

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं (एमएनपीएसपी) द्वारा दी जाने वाली पोर्ट करने की सेवाओं के लिए प्रत्येक लेनदेन पर शुल्क में करीब 66 प्रतिशत की कटौती करने का प्रस्ताव किया है। ट्राई ने मंगलवार को प्रस्ताव किया कि एमएनपी सेवा के लिए शुल्क दर 6.46 रुपये होगी। ट्राई ने बयान में कहा कि सभी टिप्पणियों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी सूचनाओं पर विचार के बाद उसने 30 सितंबर को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट लेनदेन शुल्क और डिपिंग शुल्क (दूसरा संशोधन) नियमन, 2019 जारी किया है। इसके तहत प्रत्येक पोर्ट आग्रह के लिए 6.46 रुपये का पीपीटीसी तय किया गया है। ये नियमन 11 नवंबर, 2019 से लागू होंगे। नियामक ने कहा कि दूरसंचार शुल्क (49वां संशोधन) आदेश, 2009 में प्रत्येक पोर्ट लेनदेन शुल्क (पीपीटीसी) तय किया गया है। यह प्राप्त करने वाले आपरेटर द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता से लिए जाने वाले शुल्क की सीमा है। अब इस अधिसूचना के बाद शुल्क की सीमा स्वतः घट जाएगी। हालांकि, एमएनपी के तहत ग्राहक प्राप्त करने वाले आपरेटर इससे कम शुल्क लेने को स्वतंत्र होंगे।

गांधी संकल्प यात्रा में व्यापारी प्रकोष्ठ का कार्यक्रम

इंदौर। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के महानगर मीडिया प्रभारी संतोष वाधवानी (रत्न विशेषज्ञ) ने बताया कि गांधी जयंती के दिन भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ ने प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश देने के लिए एक कार्यक्रम गांधी प्रतिमा के समक्ष आयोजित किया। प्लास्टिक मुक्त भारत कार्यक्रम का नेतृत्व नगर अध्यक्ष श्री गोपीकृष्ण नेमा और व्यापारी प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष निर्मल वर्मा घुंगरू के नेतृत्व में संपन्न हुआ। उपस्थित व्यापारी एवं आम जनता को गांधी संकल्प यात्रा के दौरान संकल्प दिलाया गया कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। इस दौरान व्यापारी प्रकोष्ठ द्वारा कपड़े की थैलियों का निशुल्क वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रकोष्ठ के नरेश फूदंवानी, सुशील गुप्ता, संतोष वाधवानी इत्यादि उपस्थित थे।

डीजीएफटी ने दाल व्यापारियों से 31 अक्टूबर तक आयात कार्य को पूरा करने को कहा

नयी दिल्ली। एजेंसी

वाणिज्य मंत्रालय ने दालों के आयातकों को इस साल 31 अक्टूबर तक अपने आयात का निर्धारित कोटा पूरा करने के लिए कहा है। इसमें विफल रहने पर भविष्य में उन्हें दालों के आयात कोटे के आवंटन से वंचित किया जा सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक व्यापार सूचना में कहा, ''सभी आयातकों से अनुरोध किया जाता है कि वे 31 अक्टूबर, 2019 तक अपने आयात कोटे को पूरा कर लें और इसमें विफल रहने पर आयातकों को भविष्य में दालों के कोटे के आवंटन से रोक दिया जा सकता है।'' डीजीएफटी ने 11 सितंबर को कहा था कि आयात 31 अक्टूबर तक भारतीय बंदरगाहों पर आ जाना चाहिए और आवंटन की वैधता अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

गोल्ड ज्वैलरी पर जीएसटी क्रेडिट की दिक्कतें होंगी दूर

ITC से पहले डिलीवरी की शर्त हटाने पर विचार करेगी सरकार

नयी दिल्ली। एजेंसी

सोने की बिक्री और टैक्स इनवॉइस जेनरेट होने के बाद भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने से परेशान ज्वैलर्स और बुलियन डीलर्स को केंद्र सरकार ने राहत का भरोसा दिलाया है। कारोबारियों की शिकायत है कि इम्पोर्टर से होलसेलर, रिटेलर या ज्वैलरी मेकर्स के बीच खरीद-बिक्री और बिल जेनरेट होने के बाद भी क्रेडिट नहीं मिल रहा और कारोबारियों से माल डिलीवर होने का सबूत मांगा जा रहा है। प्रिंसिपल कमिश्नर (जीएसटी पॉलिसी) योगेंद्र गर्ग ने मंगलवार को गोल्ड कारोबारियों को भरोसा दिलाया कि सरकार इस मुद्दे को लीगल कमेटी के सामने रखेगी और जरूरत पड़ी तो काउंसिल के जरिए नियमों में और सफाई लाई जाएगी। कारोबारियों की मांग थी कि सरकार इस बारे में तुरंत सफाई जारी करे कि दो डीलर्स के बीच बिल जेनरेट हो गया और टैक्स सरकार को चला गया तो डिलीवरी के इंतजार में इनपुट क्रेडिट रोकना कितना वैधानिक है। हालांकि सीबीआईसी अधिकारियों की दलील रही है कि हाई वैल्यू ट्रेड में बोगस ट्रेडिंग और फर्जी क्रेडिट लेने की आशंकाओं को कम करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि डीलर्स के बीच वास्तविक गुड्स की सप्लाई हुई है। द बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट योगेश सिंघल ने कहा कि हाई वैल्यू ट्रेड में कीमतों के उतार-चढ़ाव, क्षेत्रीय अंतर और सुरक्षा चिंताओं के चलते कई बार माल हफ्तों तक डिलिवरी नहीं होता। ऐसा कारोबारियों की आम सहमति से होता है और यह व्यापार व्यवहार का हिस्सा है। चूंकि इम्पोर्ट से होलसेलर, सेमी होलसेलर और रिटेलर तक हर ट्रांजेक्शन पर बिल जेनरेट हो रहा है और टैक्स भी जमा हो रहा है, ऐसे में क्रेडिट रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। कई एसोसिएशंस ने यह मांग भी रखी कि 10 करोड़ रुपये टर्नओवर तक ज्वैलर्स को भी कंपोजिशन स्कीम का फायदा दिया जाए और बिना इनपुट क्रेडिट उनसे एकाध फीसदी टैक्स लिया जाए। ऐसा होने पर उन छोटे कारोबारियों को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलने और वर्किंग कैपिटल फंसने से निजात मिल जाएगी। हालांकि सोने पर इनपुट क्रेडिट के साथ भी सिर्फ 3इ ही जीएसटी लगता है, ऐसे में सरकार कंपोजिशन स्कीम देने को लेकर उत्साहित नहीं है। बुलियन डीलर रमेश गोयल ने बताया कि इनपुट क्रेडिट की समस्या सबसे ज्यादा जॉब वर्क के मामले में पेश आ रही है। सोना दिल्ली में इम्पोर्ट होने के बाद कारीगरी के लिए कोलकाता, जयपुर, गुजरात और दूसरे शहरों में भेजा जाता है। माल आने-जाने में देरी भी होती है। अधिकारियों का कहना है कि कई बार कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान डीलर बिल जेनरेशन से लेकर डिलीवरी तक में कृत्रिम फायदों के लिए जानबूझकर देरी करते हैं।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण पाबंदी नहीं लगाएगी सरकार

मौजूदा कानून और जनजागरूकता का सहारा

नई दिल्ली। एजेंसी

सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार ने पूरी तरह रोक न लगाकर फिलहाल इसके खिलाफ अभियान को जनजागरूकता तक ही सीमित रखा है। सरकार ने साफ किया है कि पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना नहीं है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित ट्विटर हैंडल 'स्वच्छ भारत' पर सरकार ने कहा कि अभियान का मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। न्यूज एजेंसी ने सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाने जा रही है। बताया जा रहा है कि सरकार इसके इस्तेमाल नहीं करने के लिए लोगों को जागरूक करेगी लेकिन उत्पादन पर रोक के लिए कोई नहीं कानून नहीं लाने जा रही है। रॉयटर्स की खबर पर 'स्वच्छ भारत' ट्विटर हैंडल से दी गई प्रतिक्रिया में भी यही कहा गया है।

माना जा रहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था में पहले से मौजूद सुस्ती की वजह से कदम आगे बढ़ाने से बच रही है। ऑटो सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुस्ती है और लोगों को नौकरी गंवानी पड़ रही है। ऐसे में सरकार को आशंका है कि अभी प्लास्टिक उत्पादन पर रोक से स्थिति और बिगड़ सकती है। 'स्वच्छ भारत' की ओर से ट्वीट पर कहा गया, 'पीएम मोदी की ओर से 11 सितंबर 2019 को शुरू किया गया स्वच्छता ही सेवा अभियान का मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना नहीं, बल्कि इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता लाकर जन-आंदोलन बनाना है।' इस ट्वीट में पीएमओ को भी टैग किया गया है।

दो अधिकारियों ने कहा है कि प्लास्टिक बैग्स, कप, प्लेट, छोटे बॉटल, स्ट्रॉ और कुछ प्रकार के पाउच को बैन करने के लिए तत्काल कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, सरकार इसके इस्तेमाल में कमी का प्रयास करेगी। पर्यावरण मंत्रालय के वरिष्ठ नौकरशाह चंद्र किशोर मिश्रा ने कहा, 'सिंगल यूज प्लास्टिक प्रॉडक्ट्स जैसे पॉलिथिन बैग्स और स्टेरोफॉम के स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सरकार सरकार राज्यों से मौजूदा कानूनों को ही लागू करने को कहेगी। अभी बैन का कोई नहीं आदेश जारी नहीं किया जाएगा।'

सरकार के प्रस्तावित बैन ने उन कंपनियों को निराश कर दिया है जो सोडा, बिस्किट से लेकर कैचअप और शैंपू जैसे प्रॉडक्ट्स के पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करती हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने कहा कि यह फैसला कई सेक्टर्स के लिए अस्तित्व का मुद्दा बन गया है, क्योंकि विकल्प तुरंत उपलब्ध नहीं है। 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार की सरकारी अपील पर महीनों से तैयारी में जुटी ट्रेड-इंडस्ट्री अब ऐन मौके पर पसोपेश में फंस गई है। केंद्रीय पर्यावरण सचिव की इस सफाई के बाद कि सरकार सिंगल यूज आइटमों पर कानूनी बैन के बजाय जनजागरूकता पर जोर देगी, FMCG, गारमेंट और खानपान कारोबार में कन्फ्यूजन गहरा गया है। केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर से जिन 5 आइटमों पर रोक की बात कही थी उनमें कैरीबैग के अलावा प्लास्टिक और थर्मोकोल के कटलरी आइटम, पाउच, 200 मिली से छोटे बोतल, स्ट्रॉ भी थे। दुकानदार इस बात को लेकर परेशान हैं कि अधिकारियों ने कोई कार्रवाई की तो उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। ओडिसा सहित कुछ राज्यों ने सभी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने की बात कही है।केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर से जिन 5 आइटमों पर रोक की बात कही थी उनमें कैरीबैग के अलावा प्लास्टिक और थर्मोकोल के कटलरी आइटम, पाउच, 200 मिली से छोटे बोतल, स्ट्रॉ भी थे। दुकानदार इस बात को लेकर परेशान हैं कि अधिकारियों ने कोई कार्रवाई की तो उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। ओडिसा सहित कुछ राज्यों ने सभी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने की बात कही है।

दिवाली से पहले करदाताओं को बड़ा तोहफा

घट सकते हैं टैक्स स्लैब

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दिवाली से पहले करदाताओं के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। सरकार द्वारा दिवाली से पहले इनकम टैक्स की दरों में कटौती की जा सकती है। खबर के अनुसार, पांच लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर सरकार टैक्स 10 फीसदी लगाने की घोषणा कर सकती है। मौजूदा समय में यह दर 20 फीसदी है। वहीं 10 लाख रुपये से ज्यादा कमाई पर टैक्स 25 फीसदी हो सकता है। अभी यह दर 30 फीसदी है। पांच लाख की आय पर 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद बाकी 4.5 लाख पर अभी मौजूदा समय में 20 फीसदी यानी 90 हजार रुपये टैक्स लगता है। अगर यह दर घटकर 10 फीसदी हो जाती है, तो यह रकम 45 हजार रुपये हो जाएगी। यानि आपको 45,000 रुपये का फायदा होगा। यह गणना टैक्स छूट के लिए निवेश के विकल्पों और सेस के बिना है।

इतना ही नहीं, केंद्र सरकार सेस और सरचार्ज हटाने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त, कर में छूट के कुछ अन्य विकल्प भी सरकार खत्म कर सकती है। फैसला लेते वक्त सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड (DTC) की सिफारिशों को ध्यान में रखेगी। 19 अगस्त को डीटीसी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। पैनल ने सुझाव दिया है कि पांच लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगाया जा सकता है, जो अभी 20 फीसदी है। 10 लाख से 20 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स 30 फीसदी से घटकर 20 फीसदी किया जा सकता है। 20 लाख रुपये से दो करोड़ की आय पर टैक्स 30 फीसदी किया जा सकता है। बता दें कि हाल ही में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की थी, जिसके मुताबिक घरेलू कंपनियों पर बिना किसी छूट के इनकम टैक्स 22 फीसदी हो गया है। जबकि सरचार्ज और सेस जोड़कर प्रभावी दर 25.17 फीसदी होगी। पहले यह दर 30 फीसदी थी। साथ ही सरकार ने कैपिटल गेन पर भी सरचार्ज खत्म करने की घोषणा की थी।

देश का विदेशीमुद्रा भंडार 38.8 करोड़ डॉलर घटकर 482.57 अरब डॉलर

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 20 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 38.8 करोड़ डालर बढ़कर 428.572 अरब डालर रह गया। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में कमी और स्वर्ण आस्तियों के घटने के कारण यह गिरावट आई है। रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 64.9 करोड़ डालर घटकर 428.960 अरब डालर रह गया था। देश का सकल विदेशी मुद्रा भंडार इस साल अगस्त माह में 430.572 अरब डालर के अब तक के सर्वोच्च स्तर को छू चुका है। रिजर्वबैंक ने बताया कि विदेशीमुद्रा भंडार का अहम हिस्सा, विदेशीमुद्रा आस्तियां 20 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 12.5 करोड़ डॉलर घटकर 396.670 अरब डॉलर रह गया।आंकड़ों के मुताबिक समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्वर्ण आरक्षित भंडार 25.9 करोड़ डालर घटकर 27.843 अरब डालर रह गया। यह लगातार दूसरा सप्ताह है जब भारत के पास रखे बहुमूल्य धातुओं के मूल्य में गिरावट आई है।आंकड़ों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास विशेष आहरण अधिकार इस दौरान 30 लाख डॉलर बढ़कर 1.435 अरब डालर हो गया। इस दौरान कोष के पास देश का आरक्षित भंडार 60लाख डालर घटकर 3.623 अरब डालर रह गया।

रेलवे की नई पहल, मुंबई चर्चगेट स्टेशन पर लगाई रीसाइकल्ड प्लास्टिक से बनी बेंच

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

पीएम मोदी ने इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से देश से आह्वान किया था कि सभी देशवासी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर दें। जिसके बाद देखने में आया था कि देशभर में जगह-जगह प्लास्टिक प्रतिबंधित कर दिया गया था और साथ ही लोगों ने भी प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर दिया।

वहीं, भारतीय रेलवे ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार के कदम से कदम मिलाया है। भारतीय रेलवे ने एक और नई पहल की है। रेलवे ने रीसाइकल्ड प्लास्टिक से बने तीन बेंच पश्चिम रेलवे के चर्चगेट स्टेशन पर लगाए हैं। प्लास्टिक से निर्मित होने के कारण ये बेंच काफी मजबूत हैं, साथ ही वजनी भी हैं। रेलवे का कहना है कि इससे पर्यावरण को दूषित होने से बचाने में मदद मिलेगी।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।